<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सीएमडी ने सीआईआई फाइनेंसिंग 3.0 शिखर सम्मेलन में कम ऋण लागत और ग्रीन टैक्सोनॉमी के लिए इरेडा के प्रयासों पर प्रकाश डाला

मुंबई, 2 सितंबर 2024

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने आज उधार लेने की लागत को कम करने और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की बैंकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मुंबई में सीआईआई फाइनेंसिंग 3.0 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, श्री दास ने भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से विकास में ग्रीन टैक्सोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रकाश डाला।

"हरित वित्तपोषण, जलवायु जोखिम और सतत टैक्सोनॉमी : आगे का रास्ता" के बारे में अपने संबोधन में, श्री दास ने इस बात पर जोर दिया कि इरेडा का ध्यान सिर्फ अपने नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है । कंपनी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए समान रूप से समर्पित है जोकि सम्पूर्ण भारत में अक्षय ऊर्जा के समेकित विकास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय समुदाय तेजी से हरित क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर के रूप में देख रहा है, फिर भी हरित टैक्सोनॉमी की कमी व्यापक हरित निवेश के लिए एक बाधा बनी हुई है।

श्री दास ने उधार लेने की लागत को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अधीन इरेडा को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। इस समावेशन से इरेडा द्वारा जारी किए गए बॉण्ड पर पूंजीगत लाभ कर छूट मिलेगी, जिससे कम लागत वाले फंड तक पहुंच आसान होगी, जिससे पूरे हरित ऊर्जा क्षेत्र को लाभ होगा।

उन्होंने दर्शकों को यह भी बताया कि इरेडा ने डेढ़ साल पहले नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को ग्रीन टैक्सोनॉमी के बारे में एक मसौदा प्रस्तुत किया था। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है, कि जलवायु टैक्सोनॉमी जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तैयार है। श्री दास ने कहा कि इस ग्रीन टैक्सोनॉमी के कार्यान्वयन से न केवल भारत की नेट जीरो लक्ष्यों की दिशा यात्रा में तेजी आएगी, बल्कि टैक्सोनॉमी के अधीन कवर की गई गतिविधियों की एक स्पष्ट सूची प्रदान करके देश को पर्याप्त वैश्विक ग्रीन फंडिंग आकर्षित करने के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा।

हरित निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, इरेडा के सीएमडी ने घरेलू पेंशन और बीमा फंडों से प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) का 5% तक ग्रीन बॉण्ड में आवंटित करने का सुझाव दिया। इस रणनीतिक सुझाव का उद्देश्य बॉण्ड बाजारों को मजबूत करना और हरित क्षेत्र में वैश्विक और स्थानीय निवेश को बढ़ाना है।

श्री दास ने यह भी बताया कि 27% कार्यबल महिलाओं के होने के नाते , इरेडा में सीपीएसई में सबसे अधिक महिला कर्मचारी भागीदारी होने की संभावना है, जोकि समावेशी विकास के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में खुदरा और लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को वित्तपोषण की पेशकश करने की व्यवहार्यता का पता लगा रही है, जिस क्षेत्र में वर्तमान में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।